CHALAM): (a) and (b) No, Sir. For manufacture of potassium iodate, iodine, which is not being manufactured in the country is imported in bulk. Small scale units produce potassium iodate in the country.

(c) No shortage of iodised salt has been reported from any part of the country. Against the target of 7 lakh tonnes of iodised salt fixed for the year 1986-87, the actual production was 7.73 lakh tonnes. The target for this financial year has been fixed at 12 lakh tonnes. Against this target, a production of 13.8 lakh tonnes has already been achieved till January, 1988.

Workshop on Pesticides

3434. SHRIMATI ELA RAMESH BHATT: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the UNIDO had organised a workshop on pesticides through the Hindustan Insecticides Limited recently and if so, what are the details thereof;

(b) whether the HIL had given the pride of place to some members of Pesticide Association of India, including multinationals belonging to it and Indian Explosives Limited; and

(c) whether the HIL had been approached by a natonal voluntary agency to attend some sessions as observer but permission was not given and if so, what were the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) Yes, Sir. A 5-week International Training Programme on quality control of Pesticides formulation was organised as a part of PEST programme sponsored by the World Bank, FAO, UNDP and UNIDO in New Delhi in October-November, 1987. Representatives from China, Korea, Indonesia, Thailand, India and Srilanka participated in the programme.

(b) Since the selection was made by the respective countries and finally by the World Bank, the question of HIL, who were the regional coordinator for the programme, having given pride of place to anyone does not arise. There were three participants from India, none of them from Indian Explosives Limited.

(c) As it was only a 'Training Programme' and not a 'Seminar', there was no question of allowing anybody as "observer". Since HIL was only a coordinator and not a sponsorer in this programme, the question of giving permission by them does not arise.

डाकतार विभाग की जोनल स्तर पर बैठकें

3435. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार मंत्रालय/संसद सदस्यों के साथ रेल मंत्रालय की भांति जोनल स्तर पर अपनी बैठक करने का विचार रखती है ; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुत थोड़े संसद सदस्य महाडाकपाल द्वारा बुलाई गई सर्किल स्तर की बैठकों, जिनमें राज्य को सर्किल माना जाता है, में इसलिए भाग नहीं लेते क्योंकि उन्हें सार्थक नहीं समझते ; और

(ग) क्या डाकतार विभाग ने देश में राज्य स्तर पर उपभोक्ता सलाहकार समितियां बनायी हैं, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो किस मंच पर उपभोक्ताओं के लिए सुविधाओं से संबंधित मामलों पर विचार किया जाता है ?

ऊर्जा मंत्री और संचार मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी नहीं। संचार मंत्रालय में ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है। राज्य/जिला मुख्यालयों में कार्यरत डाक तथा दूरसंचार समितियां ही, जिनमें संसद् सदस्य भी प्रतिनिधि होते हैं, पर्याप्त समझी गयी हैं।

(ख) मंत्रालय की बैठकों में बहुत कम संसद सदस्यों के भाग लेने के कारणों का पता नहीं है। विभाग इन बैठकों को काफी गंभीरता से लेता है और सभी संबंधित संसद सदस्यों को इनमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उपस्थित पर ध्यान न देते हुये, कार्यसूची में शामिल मदों पर जो विचार-विमर्श होता है, वह व्यापार युक्त और सार्थक होता है।

(ग) इस समय सर्किलों में आयोजित की जा रही बैठकों में ग्राहकों की सुविधाओं से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की जाती है। इस दृष्टि से राज्य-स्तर पर ग्राहक सलाहकार समितियों के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बिहार में संचार की सुविधा का आधुनिक बनाया जाना

3436. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक संचार सुविधा के विस्तार की क्या योजना है और इसके लिए इस वर्ष क्या व्यवस्था की गई है ;

(ख) क्या बिहार संचार प्रणाली के सम्बन्ध में अन्य राज्यों से पिछड़ा हुआ है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि बिहार में अनेक जिला एक्सचेंजों को एस० टी० डी० जैसी सुविधाओं से अभी तक जोड़ा नहीं गया है यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री और संचार मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) (i) सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान 534 षटकोणों में दूर संचार सुविधाये उपलब्ध कराने की योजना है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रेडियो प्रणालियों पर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 4000 लाइने क्षमता के स्वचल एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है। मौजूदा एक्सचेंजों के उन्नयन के लिए 20 सी-डाट ग्रामीण स्वचल एक्सचेंज लगाने की संभावना है।

उपर्युक्त योजना पर आने वाला अनुमानित खर्च लगभग छः करोड़ रुपए है।

(ख) जी नहीं।

(ग) पारेषण माध्यम और स्वचल एक्सचेंज उपस्कर के अभाव में 39 जिला मुख्यालयों में से बीस जिला मुख्यालयों को एसटीडी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

Acquisition of land for Koel-Karo Hydel Project, Bihar

3437. SHRI PRITHBI MAJHI:

KUMARI SUSHILA TIRIA:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the order of acquisition of land for Koel-Karo Hydel Project in Bihar has since been issued;

(b) if so, how many acres of land will be acquisitioned;

(c) how many families of tribals will be affected partially or completely after the completion of the project and how many tribal villages will be submerged; and

(d) what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRIMATI